IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 23 | सांचौर, रविवार, 1 दिसंबर 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें विभागीय अधिकारी-कलक्टर

जालोर । जवाई नदी पुनर्जीवित की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के.

गावंडे ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने किसानों द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए मांग पत्र के संबंध में कृषि, विद्युत, सहकारिता, परिवहन, पुलिस एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को विभागीय स्तर पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण संवेदनशीलता एवं जवाबदेहिता के साथ कार्य किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष ध्यान रखते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते की समस्याओं, 72 घण्टे में जले हुए ट्रांसफॉर्मर बदलवाने, खराब विद्युत मीटर को नियत समय में बदलने, मीटर रीडिंग सही लेने, कृषि के लिए विद्युत सप्लाई दिन में करवाने, कृषि यंत्रों पर बकाया अनुदान जारी करवाने, सहकारिता विभाग द्वारा बंद किए गए बी.एम. सी. सेन्टर को पुन: शुरू करवाने, सहकार दुर्घटना बीमा एवं सहकार ऋण बीमा का भुगतान सही समय पर करवाने, ग्रामों में पेयजल व पशुधन के लिए पर्याप्त एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सहित विभिन्न मांगों पर जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए चर्चा की साथ ही विभागीय अधिकारियों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर अधिकारियों-कार्मिकों को पाबंद करने के निर्देश दिए।

नेफस्कॉब के हीरक जयंती समारोह में निमोद पैक्स हुई पुरस्कृत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नागौर । जिले की निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति को राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ की ओर से सुभाष यादव आवार्ड से पुरस्कृत किया गया । यह आवार्ड नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में NAFSCOB के हीरक जयंती समारोह एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा समिति व्यवस्थापक झुमरलाल एवं समिति अध्यक्ष खेमाराम बुगालिया को दिया गया । वही नेफस्कोब की ओर से पुरस्कृत होने के पश्चात निमोद समिति मुख्यालय पहुंचने पर निमोद एव बांसा के समिति सदस्यों द्वारा समिति अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया । इस दौरान समिति संरक्षक सलाहकार और मुख्य शिल्पी सुभाष चंद्र आर्य, समिति सदस्य मांगूराम निवाद, मनोज जांगिड़, लालचंद जांगिड़, गंगाराम जांगिड़, अर्जनराम बुगालिया, राकेश अग्रवाल एवं पूर्व सरपंच सांवलाराम बुगालिया मौजूद रहें ।

गौरतलब हैं कि निमोद सहकारी समिति को सीसीबी नागौर द्वारा पिछले 35 वर्षो से ऋण वसूली के लिए उपलब्धि प्रमाणपत्र तो अपेक्स बैंक द्वारा 2003-04 एवं 2006-07 में कार्य दक्षता पुरस्कार दिया गया, इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2011-12 का उत्कृष्ट पुरस्कार तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों में 8 दिसबंर 2012 में निमोद सहकारी समिति को प्राप्त हुआ था।

नेनोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नेनोल

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

श्री सुजानाराम देवासी
अध्यक्ष

श्री बिजलाराम देवासी
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

एकमुश्त समाधान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की सांचौर शाखा में सपर्क करें।

किसान महापड़ाव के 9वें दिन जालोर बंद के दौरान जिला पर एकत्रित हुए किसानों ने राजनीतिक उदासीनता पर नेताओं को घेरा, कहा उनकी लाचारी से जालोर का कृषि क्षेत्र नष्ट होने के कगार पर

50 साल से जालोर को नेताओं द्वारा ठगने की वजह से जिले का कृषि क्षेत्र नष्ट होने की कगार पर, किसान बोले - जवाई में हमारे हिस्से का पानी पाली की कपड़ा फैक्ट्रियों में

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में किसानों ने जवाई बांध से पानी का हिस्सा लेने को लेकर अब तक जिला मुख्यालय पर महापड़ाव जारी कर रखा हैं, किसानों द्वारा महापड़ाव के 9वें दिन किसानों की वाजिब मांगो के निस्तारण के लिए जालोर बाजार पूर्ण बन्द रहा, इस दौरान फल-सब्जी, दूध, किराणा आदि रोजमर्रा की आवश्यकता से जुड़ी सामग्री की दुकानों समेत सभी प्रकार की दुकानें बन्द रही। साथ ही दिन में कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या का सामने करने वाला पुराना बस स्टैंड सुनसान नजर आया। जिससे लॉकडाउन से जुड़ी यादें ताजा हो गयी। ज्ञातव्य है कि लॉकडाउन में भी बाजार बंद रहने से लोगो की चहल पहल नही होने के कारण बाजार सूने रहे थे। वही महापड़ाव के 9वें दिन किसानों ने जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा, और कहा 50 साल में राजनीतिक लाचारी ही जालोर के कृषि क्षेत्र के चौपट होने का कारण बनी। हर साल चुनावी माहौल में नेता आश्वासन देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। किसान नेता अर्जुनसिंह सुराणा ने कहा कि जालोर का हक पाली जिले ने मारा है। पेयजल स्कीम के नाम पर जनता को ठगा गया है। हकीकत में जालोर के हिस्से का यह पानी जालोर में पेयजल स्कीम्स से कई अधिक वहां की कपड़ा फैक्ट्रियों में केमिकल युक्त कपड़ों की धुलाई में उपयोग आ रहा है। इसी के कारण जालोर को पानी नहीं मिल रहा। नदी में पानी तभी छोड़ा जाता है जब उसे बांध में रोक पाना संभव नहीं होता। किसान नेता रतनसिंह कानीवाड़ा ने कहा कि नेताओं की उदासीनता जालोर के पूरे कृषि क्षेत्र के नष्ट होने का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि जालोर जिला डार्क जोन में है। बारिश भी कम हो रही है। नदी में पानी नहीं मिलने से करीब 200 किमी दायरे के सभी जवाई क्षेत्र के सभी कुएं सूख चुके हैं। किसान नेता बद्रीदान नरपुरा ने कहा कि जवाई हो या माही परियोजना जालोर को हक का पानी मिलना चाहिए। इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। महापड़ाव को बाबूलाल जाखड़ी, राणसिंह मेडा, सोनाराम, सेवाराम, पाबूराम विश्नोई, सांवलाराम, छैलसिंह, प्रभुराम, चंदनसिंह मोरसीम, विक्रमसिंह, जीवाराम समेत कई किसान नेताओं ने संबोधित किया

ट्रेक्टरों में बिस्तर और ईंधन के साथ किसान पहुंचे

किसान नेता रतनसिंह कानीवाड़ा ने कहा कि हर बार चुनावी माहौल में जालोर की जनता को जवाई बांध से पानी दिलवाने का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन उसके बाद नेता भूल जाते हैं। इस बार हक तय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में किसान महापड़ाव के तहत अपने स्तर पर बिस्तर और ईंधन के लिए लकड़ियां भी साथ लेकर पहुंचे। आंदोलन के दौरान दिनभर उठापटख चली, चर्चा के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं पहुंचा।

जालोर बंद सफल

वहीं जवाई बांध के पानी पर हक निर्धारण और नदी प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ने की मांग को लेकर जारी आंदोलन के तहत बुधवार को भारतीय किसान संघ के आह्वान पर घोषित जालोर बंद सफल रहा। महापड़ाव के तहत जालोर बंद को सभी संगठनों का समर्थन मिला। वहीं जिलेभर में इसका बड़ा असर देखने को मिला।

रिटायरमेंट के बाद सोसायटी को दें अनुभवों का लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सांचौर । प्रत्येक सेवा में आए हुए हर अधिकारी-कर्मचारी की एक निश्चित समय के बाद सेवानिवृति होती है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन रिटायर होने के बाद व्यक्ति खुद के लिए समय निकाल पाता है। उसे यह जीवन अपने तरीके से जीते हुए अपने शौक पूरे करना चाहिए। यह बात जालोर सीसीबी शाखा सांचौर प्रबंधक नवीन कुमार सक्सेना ने कही। वे शाखा कार्यक्षेत्र की हाड़ेतर ग्राम सेवा सहकारी समिति पदस्थ व्यवस्थापक वगताराम चौधरी के रिटायरमेंट पर शाखा परिसर में आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। वही कार्यकारी ऋण पर्यवेक्षक लक्ष्मणाराम पुरोहित ने कहा कि सोसायटी के सेवाकाल में व्यवस्थापक के पास कई तरह के अच्छे बुरे अनुभव आते हैं। जिसके जरिए वह

सोसायटी को नई दिशा दे सकता है। उन्होने कहा कई लोग रिटायरमेंट के बाद गुमनाम व चिंता में जीवन बिताते हैं, यह अच्छे लक्षण नहीं हैं। इसके ठीक उलट व्यक्ति को बचा जीवन खुशी व सुख से जीना चाहिए। इस दौरान हाड़ेतर सहकारी समिति अध्यक्ष सवाराम चौधरी, बैकिंग सहायक गगन मीणा, कार्यकारी ऋण पर्यवेक्षक पोकाराम विश्नोई, लुबाराम चौधरी, नागजीराम चौधरी, जयरुपाराम देवासी, पूनमाराम विश्नोई, भगराज मांजू, छेन्दाराम, हरचंद देवासी, गजेन्द्रसिंह चंपावत, वासुदेव पुरोहित, दशरथ कुमार पुरोहित, बिजलाराम देवासी समेत स्टाफ के अन्य लोगों ने चौधरी की समय की पाबंदी व समर्पण भाव से कार्य करने की प्रशंसा करते हुए औरों को प्रेरणा लेने की बात कही। वही कार्यक्रम में पैक्स एवं बैंक स्टाफ की ओर से वगताराम चौधरी को पट्टू ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर संमानित किया गया । अंत में व्यवस्थापक यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष बाबुलाल विश्नोई ने उपस्थित सभी कर्मचारियों सहित बैंक स्टॉफ का धन्यावद ज्ञापित किया ।

सहकारी भर्ती बोर्ड की नाकामी को छुपाने का मिला नया जरिया

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सुनने में जरुर अटपटा लग रहा होगा लेकिन यह हकीकत हैं कि सहकारिता विभाग ने राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की नाकामी को छुपाने के लिए एक नया जरिया निकाल दिया हैं, विभाग के पंजीयक कार्यालय ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संविदा कार्मिक की नियुक्ति को लेकर एक नया आदेश जारी किया हैं, जिसके मुताबिक जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियां में अन्य समितियों के व्यवस्थापक को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ हैं, अब उन समितियों में सेवाप्रदाता संस्था के माध्यम से संविदा कार्मिक की नियुक्ति की जा सकेगी, लेकिन संविदा कार्मिक को 1 लाख रुपए की फिडेलिटी गारंटी और 2 गणमान्य व्यक्तियों की जमानत देनी होगी, जिसके पश्चात उस संविदा कार्मिक को व्यवस्थापक का कार्यभार दिया जाएगा । ऐसे में अब जहां राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती की जो मांग स्थानीय स्तर पर चल रही थी, वह काफी हद तक दब जाएगी और जिस प्रकार पिछले आठ सालों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पाई वही अब इस फरमान से ऐसा लग रहा हैं कि आने वाले कई सालों तक व्यवस्थापक के रिक्त पदों पर सहकारी भर्ती बोर्ड भर्ती नहीं करवा पाएगा । क्योकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संविदा कार्मिक की नियुक्तियां हो जाएगी और पूर्ववर्ती सरकार की तरह चुनावी साल में संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी का पुनरुद्धार किया जाएगा ।

समीक्षा बैठक में उठी मांग

सहकारिता विभाग के पंजीयक कार्यालय ने इस नियुक्ति आदेश के लिए केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना को आधार बनाया है। सहकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की समीक्षा बैठक 12 नवंबर 2024 को आयोजित करवाई गई, इस दौरान सीसीबी प्रबंध निदेशकों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पूर्णकालीक व्यवस्थापक नहीं होने का मामला सहकारिता विभाग के संज्ञान में लाया, जिसके पश्चात यह आदेश जारी हुआ है।

चर्चा में रहती है सहकारी समितियों

प्रदेश में करोड़ो के गबन और अनियमितताओं को लेकर राजस्थान विधानसभा से लेकर सहकारी गलियारों तक चर्चाओं में रहने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद पर संविदा कार्मिक को नियुक्त कर करोड़ो के व्यवसाय की बागडोर थमाई जाएगी, इस आदेश के जारी होने के बाद कई सेवानिवृत्त पैक्स कार्मिकों से लेकर वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों ने अपने दांवपेच लगाने शुरु कर दिए हैं और अपने चहेतों को अतिरिक्त कार्यभार वाली समिति में नियुक्ति दिलाने की दौड़-धूप शुरु कर दी हैं

सहकारिता मंत्री के आदेशों की पालना में रजिस्ट्रार ने कसा शिकंजा

सहकारी अधिनियम के तहत धारा-55 के जांच एवं 57 के सरचार्ज प्रकरणों में देरी करने वाले अधिकारियों को जारी किये नोटिस

- अक्टूबर माह में धारा-55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी
- धारा-57(1) के 318 प्रकरणों में से 91 प्रकरणों में जांच पूरी कर ली गई है और धारा-57(2) के 232 प्रकरणों में से 89 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित
- जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जांच परिणाम जारी नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । प्रदेश में सहकारी सोसायटियों के गठन, उनके द्वारा किये गये कारोबार और वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाडे को रोकने तथा सोसायटियों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सहकारी अधिनियम के तहत धारा-55 एवं 57 के तहत त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल ने दिये ताकि सहकारी सोसायटियों के गठन से मिलने वाले लाभों से उनके सदस्य वंचित न रहें। श्रीमती राजपाल ने सहकार भवन स्थित कमेटी रूम से रिव्यू करने के बाद बताया कि अक्टूबर माह में धारा-55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार धारा-57(1) के 318 प्रकरणों में से 91 प्रकरणों में जांच पूरी कर ली गई है और धारा-57(2) के 232 प्रकरणों में से 89 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित कर दिया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार ने बताया कि एक माह की अवधि में भी जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जांच परिणाम जारी नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सहकारी सोसायटियों में किसी प्रकार की अनियमितता या कोताही को स्वीकार नहीं किया जायेगा। जांच में देरी होना अप्रत्यक्ष रूप से दोषी व्यक्ति को प्रश्रय देने के समान होता है, जिससे सोसायटियों का संचालन प्रभावित होता है और सदस्य सहकारिता की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। सहकारिता रजिस्ट्रार ने कहा कि जिन प्रकरणों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है,उन्हें प्राथमिकता से जारी किया जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी खण्डीय पंजीयक अपने स्तर पर लगातार नियमित रूप से मॉनिटरिंग करके जांच कार्य में तेजी लावे और उनका निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने खण्डीय पंजीयकों को निर्देश दिये कि बिना किसी ठोस कारण के जांच कार्य में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे। गौरतलब है कि सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा माह अक्टूबर में की गई सहकारी अधिनियम के तहत धारा-55 एवं 57 के तहत समीक्षा के दौरान लम्बे समय से पेंडिंग चल रही जांचों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये थे।

धारा-55 में जांच

किसी भी सहकारी सोसायटी के संचालक मण्डल के निर्णय या सोसायटी के 10 प्रतिशत सदस्यों के आवेदन पर सोसायटी के गठन, कारोबार और वित्तीय स्थिति के बारे में धारा-55 में जांच करवाई जा सकती है। यदि सोसायटी में अनियमितता संबंधी प्रकरण रजिस्ट्रार के संज्ञान में आता है तब रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से जांच करवा सकता है।

धारा-57 में सरचार्ज

किसी भी सहकारी सोसायटी के संगठन या प्रबंधन में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि नियमों या उपविधियों के विरूद्ध कार्य किया हो, सोसायटी की आस्तियों में कमी कर दी हो या सोसायटी के धन का दुरूपयोग कर लिया हो या उसको हडप लिया हो, ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या पदाधिकारी के विरूद्ध धारा 57 में आचरण की जांच कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है।

गांवों में कर्जदार ज्यादा

वर्ष 2022-23 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को आधार बनाकर पिछले दिनों सांखियकी मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण रिपोर्ट एक बार फिर शहरों की तुलना में गांवों में कर्ज के बढ़े भार के बारे में बताती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में प्रति एक लाख लोगों में 18,714 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज ले रखा है, जबकि शहरों में गांवों से कुछ कम 17,442 लोग कर्जदार हैं. ग्रामीण महिलाओं पर भी कर्ज का बोझ अधिक है. गांवों में एक लाख महिलाओं पर 13,016 महिलाएं कर्ज में डूबी हैं. जबकि शहरों में 10,584 महिलाएं ही कर्जदार पायी गयीं. गांवों में कर्ज बढ़ने का कारण यह है कि वहां शहरी जीवन का अनुकरण होने लगा है, चाहे वह घरेलू जरूरतें हों, बच्चों की शिक्षा हो या फिर खान-पान और पहनावा. गांव के लोगों के शहरों में कार्यरत होने से ग्रामीणों के लिए कर्ज की उपलब्धता भी आसान हुई है. रिपोर्ट बताती है कि शहरों में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई सुविधाएं निःशुल्क मिल जाती हैं, जबकि गांवों में इनके लिए पैसे देने पड़ते हैं. इसलिए ग्रामीणों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है. इससे यह भी पता चलता है कि गांवों का जीवन शहरी जीवन की तुलना में अब भी कितना कठोर है. गांवों से शहरों की तरफ पलायन इसी कारण रुका नहीं, बल्कि अनवरत जारी है. सरसरी तौर पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाली भले लगे, लेकिन यह सच्चाई पिछले अनेक वर्षों से जारी है कि शहरों की तुलना में गांवों के लोगों पर कर्ज का बोझ ज्यादा है. वर्ष 2016 में आयी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में 31.4 फीसदी परिवारों ने कर्ज ले रखा था, जबकि शहरों में 22.4 परिवार कर्ज में डूबे थे. वह आंकड़ा यह भी बताता था कि गांवों में पेशेवर (बैंक) और गैर पेशेवर (साहूकार आदि) संस्थाओं से कर्ज लेने की दर क्रमशः 56 और 44 प्रतिशत थी. जबकि शहरों में ज्यादातर कर्ज बैंकों से लिये गये थे. वर्ष 2021 में आयी राष्ट्रीय सांखियकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट भी बताती थी कि महामारी से पहले 22.4 फीसदी शहरी परिवारों की तुलना में 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे थे. उस रिपोर्ट ने इस सच्चाई की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया था कि महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने पर लोग शहरों से गांवों में पहुंचे, तो वे और कर्ज में डूब गये थे. इस तरह की रिपोर्टों के लगातार आने का अर्थ यही है कि ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए अभी और बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है.

नीतिगत क्रियान्वयन से सहकारिता को बढ़ावा

शाजी के.वी, अध्यक्ष नाबार्ड

भारत में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली प्रारंभिक शक्तियां भले ही अब कमज़ोर पड़ रही हों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस समय कई नई और जटिल उभरती चुनौतियां हैं, जिनके लिए सहकारी आंदोलन को नई दिशा और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह इसलिए भी जरूरी है,

साझा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास रणनीति सहकार से समृद्धि के देश में अब तक काफी कारगर नतीजे सामने आए हैं। स्वतंत्रता से पहले के दौर में अगर हम भारत में सहकारिता आंदोलन की उत्पत्ति को देखें तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत किसानों की गरीबी कम करने की चुनौती से हुई थी, जिसका मुय कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा और साहूकारों की सूदखोरी प्रवृत्ति था। एनएएफआईएस, 2021-22 के अनुसारयह काफी प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार की निरंतर और लक्षित वित्तीय समावेशी पहलों के कारण, ग्रामीण परिवारों की साहूकारों और जमींदारों पर निर्भरता अब घटकर मात्र 4.2 प्रतिशत रह गई है। भारत में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली प्रारंभिक शक्तियां भले ही अब कमज़ोर पड़ रही हों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस समय कई नई और जटिल उभरती चुनौतियां हैं, जिनके लिए सहकारी आंदोलन को नई दिशा और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो सपना देखा है, उसी के अनुरूप देश 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इन नई चुनौतियों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एक कुशल ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हासिल करना,स्थायीआधार पर खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादकता तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रयासों को बढ़ाना और डिजिटल क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना शामिल है। सहकारी संस्थाएं अपने मजबूत स्थानीय ज्ञान, पूर्व की घटनाओं से अनुभव हासिल कर भविष्य की नई योजनाएं, संपर्क कार्यक्रम बनाने तथा इन्हें मजबूत करने की क्षमता और नए कारोबारी माहौल के अनुरूप ढलने के कारणइन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती हैं। सहकारी संस्थाओं के लिए मददगार नीतियां बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'सामाजिक विकास में सहकारी समितियों पर रिपोर्ट' (जुलाई 2023) से जानकारी प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है, जो इस बात पर ज़ोर देती है कि सहकारी समितियां बाज़ार संबंधी विफलताओं से निपटने, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, रोज़गार के अवसर बढ़ाकर सतत विकास को सहारा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह रिपोर्ट सहकारी समितियों के लिए एक उद्यमी प्रक्रियागत दृष्टिकोण की सिफारिश करती है, जो एक स्थानीय माहौल मेंआपस में जुड़े हुए नेटवर्क के माध्यम से सभी हिस्सेदारों को जोड़ती है। भारत के सहकारी क्षेत्र में दूध और चीनी के क्षेत्रों में मिली अपार सफलता केवल एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को ही प्रमाणित करती है। इसका एक और अन्य सफल उदाहरण भारत की सबसे पुरानी श्रमिक सहकारी संस्था - उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का है, जो बुनियादी ढाँचे से जुड़ी है और इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है। यह वैकल्पिक उद्यमशीलता मॉडल का एक अनूठा उदाहरण है। यहां सहकारिता के दो विशिष्ट पहलुओं का उल्लेख करना आवश्यक है:

पहला, सहकारी समितियों के बीच सहयोग का महत्व-जब उरालुंगल को एक सड़क परियोजना हेतु लिए गए भारी कर्ज की किश्तें चुकानी थीं, तो उसने 38 प्राथमिक सहकारी समितियों का एक संघ बनाया और उनकी मदद से यह भारी राशि जुटा सकी, जिससे उसकी साख भी बनी रही और साथ ही उसका विस्तार भी हुआ; दूसरा, निजी फर्मों के विपरीत,संकट की स्थिति में एक श्रमिक सहकारी समिति द्वारा रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। श्री अमित शाह के शानदार नेतृत्व में भारत सरकार में एक नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के लिए भारत में हाल की नीतियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उभरती चुनौतियों की व्यापक और जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। इस तरह के कुछ बड़े प्रयासों में कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स का गठन, इसे कंप्यूटरीकृत करना, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और पैक्स के लिए खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट/एलपीजी वितरण अधिकार; सहकारी क्षेत्र में गोदामों का व्यापक नेटवर्क; मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन; शामिल नहीं की गई पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियांऔर पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी समितियों के लिए अपने बहुस्तरीय और गतिशील रूप से उत्तरदायी सहयोगात्मक ढांचे के साथ, मंत्रालय के मार्गदर्शन में, सतत प्रक्रिया के रूप में नीति क्रियान्वयन से जुड़े लोगों को सक्षम बनाता है जिसमें **(अ)** ग्रामीण सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तपोषण का प्रावधान, कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण देने के लिए उनके संसाधनों में पूर्ति करना; **(ब)** सहकारी विकास निधि के माध्यम से विकासात्मक समर्थन और वित्तीय समावेशन निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना; **(स)** नीति और कार्यान्वयन समर्थन, जैसे पैक्स का केप्यूटरीकरण और 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने वाले सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में पैक्स का कार्यान्वयन, और **(द)** वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिएपर्यवेक्षण जैसे प्रयास शामिल हैं। नाबार्ड सहकारी समितियों को एक-दूसरे के तुलनात्मक लाभों से लाभान्वित करने की सुविधा प्रदान कर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में वित्तीय पक्ष से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु-सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के मौजूदा बैंक खातों को विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में समेकित करना और उन्हें एक केंद्रीकृत जिला/राज्य सहकारी के तहत रखना होगा, जिससे सहकारी प्रणाली के संसाधन प्रणाली के भीतर ही बने रहेंगे। भविष्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हाल के वर्षों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दुग्ध क्षेत्र की तर्ज पर इन तीनों वस्तुओं के लिए अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन और एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला मदद कर सकती है। आंतरिक तौर पर पूंजी निर्माणया सहकारी समितियों की आय को उनके भीतर ही बनाए रखना इन समितियों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना बनाने में मददगार साबित हो सकता है। यह उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के बढ़ते महत्व को देखते हुए उपयोगी होगा। उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे को देखते हुए बागवानी फसलों की बिक्री से होने वाले लाभों के मद्देनजरविशेष रूप से बहु-राज्य सहकारी समितियों को उत्पादकों का एक व्यापक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता हो सकती है। यह लागत को कम करने और उनकी मोलभाव करने की क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। भूमि स्वामित्व पर किसी भी जोखिम के बिना सहकारी समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि पूलिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे सकती है। WTO के अनुरूप प्रसंस्कृत उत्पादएक मजबूत कृषि-निर्यात उत्पाद क्षेत्र बनाने में मदद करने, तकनीक अपनाने, अधिक पारदर्शिता के साथ व्यापार करने में आसानी; प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माणऔर उद्यमी कारोबारी तंत्र के विभिन्न हिस्सों के रूप में कृषि स्टार्ट-अप के साथ अंतर्संबंधों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को उत्कृष्टता संबंधी प्रदर्शन से जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए संसाधनों और उत्कृष्टता परिणामों के अंतिम उपयोग की जानकारी के साथ एक मजबूत डेटा बेस विकसित करने की आवश्यकता होगी। ऋण क्षमता के आकलन के आधार पर कृषि ऋण के लिए वर्तमान आपूर्ति-आधारित दृष्टिकोण को धीरे-धीरे अंतिम उपयोग और परिणामों से संबंद्ध प्रतिबद्धताओं के आधार पर ऋण की प्रभावी मांग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों को नए उभरते नवप्रवर्तकों या नए कारोबारी विचारों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने, वित्तीय और अतिरिक्त सहायताएं देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता भी हो सकती है। नीतिगत पोषण से प्रेरित एक पुनर्जीवित सहकारी आंदोलन देश में अधिक समावेशी ग्रामीण आर्थिक समृद्धि का अग्रदूत हो सकता है।

(यह लेखक के स्वय के विचार हैं)

पैक्स सदस्यों को जागरुकता कार्यक्रम में मिलेगी सहकारिता की प्रमुख पहलों की जानकारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिले में सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर द्वारा जिले की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में केंद्रीय सहकारी बैंक के सहयोग से सहकार से समृद्धि विषय पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें है। जिसमें कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु जागरूकता सत्र: कार्यक्रम में सहकारी समितियों के सदस्यों को भारत सरकार की ''सहकार से समृद्धि'' पहल और इसके 54 कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

वही कार्यक्रम में छूटी हुई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना से लेकर कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में PACS, खुदरा पेट्रोल / डीजल दुकानें, एलपीजी डिस्ट्री यूटरशिप, जन औषधि केंद्र आदि जैसी नई पहलों के बारे में बताया जा रहा हैं ।

इस पहल की शुरुआत भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने की मंशा से की है। जिसमें सहकार से समृद्धि पहल के तहत राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के माध्यम से विभिन्न राज्यों के चार जिलों में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक पाइलेट परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं, इसके लिए प्रदेश के जोधपुर जिले का चयन किया गया है।

वही सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर के द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जोधपुर के सहयोग से जोधपुर जिले की 71 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन किया गया,

जिनमें 35000 सदस्यों को सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई प्रमुख पहलों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थान द्वारा 5 मास्टर ट्रेनर्स व 5 कोर्डिनेटर्स का चयन किया गया, जो संस्थान द्वारा प्रशिक्षित है। जिन्हे ग्राम सेवा सहाकरी समिति मुख्यालय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देशित किया गया है।

35000 सदस्यों को सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख पहलों के बारे में किया जा रहा जागरूक

71 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित आयोजित किए गए शिविर

सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर द्वारा जोधपुर सीसीबी के सहयोग से चाबा, गगाडी, नेवरा, बिराई, भटिण्डा, आगोलाई, जाटीपुरा, लोर्डिया, बिलाड़ा वृहत, गंगाणी, भालूकलां, जालोंड़ा, बोरुन्दा, पूनिया की बासनी, निबा का गांव, रडकापुरा, जैतीवास, बोरानाड़ा, बांवरला, बाराखुर्द, सामराऊ, चेनपुरा, पिचियाक, जोबा, बेरू, बैठवासियां एवं बोयल, बालरवा, शुभदण्ड, ननेउ, दईकडा, चौकडीखुर्द, कानसिंह की सिड, भुंगरा, रियां, गोपासरिया, मोगड़ाकलां, धोलिया, बिरानी, पाल, पूनासर आऊ, बड़ला बासनी, रोहिचाखुर्द, शेरगढ़, देवातड़ा, चाडी, मथानियां, सालावास, सुवालिया, जानादेसर, चाखु, चांदसमा, रामपुरा भाटियान, सरेचा, नारनाड़ी, लोहावट जाटावास, देचू, जुड, शिकारपुरा, केरु, मोरिया मूंजासर, कलाऊ, उमेदनगर, नान्दड़ा कलां, झालामण्ड, दयाकौर, प्रहलादपुरा, माणकलाव, सतलाना, जाजीवाल खिचियान में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किए गए

चाँदसमा सहकारी समिति पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

हनुमानसिंह राजावत को मिली राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रतिनिधित्व की कमान

हनुमानसिंह राजावत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों का नया यूनियन बनाने के लिए पिछले 6 माह से प्रयासरत 15 सदस्यीय कमेटी की भागदौड़ के बाद मूलत: ट्रेड यूनियन राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जयपुर श्रम विभाग राजस्थान से पंजीकृत होने के पश्चात आज इसकी जयपुर में प्रदेश स्तर की मीटिंग आयोजित की गई । इस दौरान राज्यभर के 21 जिलों से प्रतिनिधित्व की मौजूदगी में जालोर जिले की हरजी ग्राम सेवा सहकारी समितिके व्यवस्थापक हनुमानसिंह राजावत को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, साथ ही राजावत को ही प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के लिए अधिकृत किया गया, तत्पश्चात अपने संबोधन में हनुमानसिंह राजावत ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी निरतंर मेहनत कर किसानों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कार्यशील है और इन ही कर्मचारियों की बदौलत विभागीय योजनाएं धरातल पर लागू हो पाती हैं । उन्होने कहा कि संगठन के माध्यम से कर्मचारियों की वाजिब मांगों के समाधान के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी । इसके अलावा आने वाले समय में पैक्स कर्मियों को नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा । इसके लिए प्रदेश भर में संभाग लेवल पर कार्यशाला आयोजित करवाकर कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ उनकी समस्याओं को सुनकर वाजिब मांगों को सरकार एवं विभाग के समक्ष यूनियन के जरिए रखकर समयबद्धता से निस्तारण की पहल की जाएगी ।

वही श्री राजावत के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मीटिंग में उपस्थित जिला प्रतिनिधियों ने साफा एवं माल्यार्पण कर बधाई दी, इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा, सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन यूनिट बाड़मेर के महासचिव भंवराराम चौधरी, जालोर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष मांगीलाल विश्नोई सहित जालोर जिले की सराणा जीएसएस अध्यक्ष राणसिंह बालोत, देबावास जीएसएस अध्यक्ष बाबुसिंह, वेड़िया जीएसएस अध्यक्ष गोविन्दसिंह राठौड़, धुम्बड़िया जीएसएस अध्यक्ष मादाराम चौधरी, पाली जिले की बरवा जीएसएस अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित और झालावाड़ से रामचन्द्र नागर, फलौदी से भोमसिंह भाटी ने भी बधाई दी हैं, इसी तरह प्रदेश के विभिन्न पैक्स कर्मियों की ओर से निरंतर बधाईयां दी जा रही है।

मीटिंग में इनकी रही मौजूदगी

यूनियन की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में नागौर से भंवराराम चौधरी, डूंगरपुर से हेमंत व्यास, बांसवाड़ा से महिपाल सिंह, उदयपुर से मदन मेनारिया, श्रीगंगानगर से गिरधारीलाल शर्मा/जसवंत पचार, अनूपगढ़ से हेतराम भूकर, दौसा से रमेश भारद्वाज/विजेंद्र शर्मा, अलवर से देवेंद्र कुमार सैदावत, प्रतापगढ़ से लोकेंद्र सिंह, शाहपुरा से गजानंद कुमावत, भीलवाड़ा से सत्यनारायण तिवारी, सीकर से दुर्गा सिंह, नीमकाथाना से अमर सिंह, चूरू से पवन कुमार पूनिया, डीडवाना से बलदेवाराम गेट, सलूम्बर से नरपत सिंह, टोंक से शिवचरण शर्मा, चित्तौड़गढ़ से देवेंद्र सिंह शक्तावत, बारां से संदीप गोचर और राजसमंद से रोशन कुमावत उपस्थित रहें ।

संगठन के माध्यम से निरंतर सक्रिय राजावत

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत वर्ष 2016 से निरतंर संगठन के माध्यम सक्रिय बने हुए हैं, उनके प्रतिनिधित्व की शुरुआत वर्ष 2016 में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई जालोर में महामंत्री बनने के साथ हुई, जिसके पश्चात इनको वर्ष 2020 में इसी संघ में जालोर इकाई का जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ता चुना गया, जिसके बाद वर्ष 2021 में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ में सक्रियता को देखते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने इनको बतौर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोनित किया था। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष वैष्णव के नेतृत्वकाल में श्री राजावत को क्रियाकलापों का बारीकी से सानिध्य मिला था ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134

Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

सहकार नेता आमेरा ने पैक्स कर्मियों का कैडर निर्धारण करने और सीसीबी नागौर में 16वां वेतन समझौता लागू करने की उठाई मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नागौर । जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओ का विजिट कर संगठनात्मक बैठक में आने पर ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऐपलाइज यूनियन के प्रांतीय महासचिव, सहकारी साख समितियां ऐपलाइज यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया को ऑपरेटिव बैंक एंपलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य में सहकारी साख आंदोलन की मजबूती से किसान की खुशहाली के लिए सहकारिता की आधारभूत ईकाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) को आर्थिक सुदृढ़ता व सक्षम बनाया जाना सबसे बड़ी जरुरत है । सहकार नेता आमेरा ने कहा कि आज त्रि-स्तरीय सहकारी साख ढाँचे में एक ओर समिति कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, वही दूसरी ओर सहकारी बैंक करोड़ों का आयकर भुगतान कर रहे है जो सहकारिता दर्शन की विरोधाभासी स्थिति को दर्शाता है । उन्होने सरकार एवं सहकारी विभाग से पैक्स कर्मियों के परिवार पालन के लिए नियमित मासिक वेतन भुगतान की प्रामाणिक व्यवस्था के लिए पैक्स में कैडर लागू करने की मांग दोहराई हैं । साथ ही पैक्स, लैंपस, मिनी बैंक एवं सहकारी बैंकों में अनियमितता, गबन, घोटाले, आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग के रोकथाम एवं सुशासन के लिए आंतरिक निरीक्षण, नियंत्रण, परीक्षण, अंकेषण की प्रामाणिक व प्रभावी व्यवस्था पुनः लागू किया जाना एवं प्रबंधन की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय किया जाना बहुत जरुरी हो गया हैं ।

नागौर सीसीबी को हुए नुकसान की निष्पक्ष जांच कर प्रभावी समाधान जरुरी ; सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने अपने प्रेस बयान में प्रदेश के सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता, सक्षमता व बेहतरी के लिए रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के जारी दिशा निर्देश की पालना में फिट एंड प्रॉपर मानदंडो के तहत योग्य, ईमानदार एवं जवाबदेह प्रबंध निदेशक लगाए जाने की मांग दोहराई हैं, उन्होने सहकारी बैंकों में टू-टियर बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, सरकार एवं विभाग से नागौर सीसीबी में पूर्व बैंक प्रबंधन द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता, आपाधापी, अनुचित आर्थिक भुगतान, दोषपूर्ण ऋण वितरण से नागौर सीसीबी को हुए नुकसान की निष्पक्ष जाँच कर प्रभावी समाधान की जरुरत बताई है ।

रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती की मांग

आमेरा ने सहकारी बैंकों में लेबे समय से रिक्त पड़े कर्मचारी एवं अधिकारी के पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से प्रामाणिक व पारदर्शी भर्ती किए जाने, नागौर सीसीबी सहित लंबित सभी बैंकों में 16वाँ वेतन समझौता लागू करने, नागौर सीसीबी में रिव्यू डीपीसी बैठक सहित सभी सीसीबी में लंबित डीपीसी बैठक करने, सहकारी बैंक कर्मियों को बकाया व लंबित 15 दिवस समर्पित अवकाश नक़द भुगतान, रिटायरमेंट पर देय 300 दिवस उपार्जित अवकाश भुगतान सहित जेएआईआईबी व सीएआईआईबी वेतन वृद्धि भुगतान यथावत रखने की सरकार व विभाग से पुरज़ोर मांग की है ।

बैंक कर्मियों के आंदोलन की रूपरेखा की जाएगी तय

सूरजभानसिंह आमेरा ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंको में व्याप्त कुशासन व आपाधापी तथा नियमानुसार सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को देय लंबित आर्थिक भुगतान को लेकर बैंक कर्मियों में भारी असंतोष व्याप्त है, इसके लिए शीघ्र ही संगठन की प्रान्तीय बैठक जयपुर में आहुत करवाकर सहकारी बैंक कर्मियों के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी ।

जगह-जगह सहकार नेता का किया स्वागत

डीडवाना स्थित होटल क्लार्क में सहकार नेता आमेरा के स्वागत अभिनंदन के लिए समारोह आयोजित कर जिले के बैंक एवं पैक्स कर्मियों ने माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया । आमेरा ने नागौर जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं एवं निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी विजिट किया । वही सहकार नेता आमेरा का जिले में जगह-जगह शाखाओं एवं पैक्स कर्मियों द्वारा स्वागत कर अपनी वाजिब मांगो से अवगत कराया गया । डीडवाना में दीपक शर्मा, सुरेश अग्रवाल, संजय पारीक, हेमंत जोशी, मिश्रीलाल, गणपत कूकना, कमल महला, गोपाल शर्मा, शुभाष आर्य, अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधियों ने स्वागत किया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सरकार का निर्देश

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सरकार का निर्देश- आधार से जुड़ी ओटीपी के जरिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय रहे, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार से जुड़ी ओटीपी के जरिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय रहे। इसका उद्देश्य अधिकाधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस वर्ष के बजट में घोषित नियोजन-आधारित आर्थिक प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाना है। पहले चरण में, नियोक्ताओं को इस महीने की 30 तारीख तक सभी कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करना होगा। दूसरे चरण में, तस्वीर और बायोमीट्रिक विवरण की पुष्टि की जाएगी। इससे कर्मचारियों को पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की ऑनलाईन सुविधा मिलेगी और भविष्य निधि खातों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा।

चार वर्ष में और डेढ़ सौ जिलों में बनेंगे सहकारी बैंक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की संपूर्ण तरक्की के लिए सहकारी बैंकों से आगे आने का आग्रह किया। कहा कि अभी देश के तीन सौ जिलों में सहकारी बैंक हैं। चुनाव में जाने से पहले इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि करनी है। अमित शाह भारत मंडपम में राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह व ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सभी जिलों में सहकारी बैंकों की स्थापना तभी हो पाएगी जब दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बना ली जाएंगी। मतलब प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स बन जाएंगी।

राज्य की हर समस्या स्टेट को-आपरेटिव बैंक की होनी चाहिए

अमित शाह ने पैक्सों के दायित्व का भी जिक्र किया और कहा कि सहकारिता के भाव को संबल देने के लिए पैक्सों और सहकारी बैंकों को भी आगे आना चाहिए। गांव की हर समस्या पैक्स की होनी चाहिए। जिले की समस्या को-ऑपरेटिव बैंक और राज्य की हर समस्या स्टेट को-आपरेटिव बैंक की होनी चाहिए। सहकारिता को जनविश्वास भी अर्जित करनी होगी। इसके लिए पारदर्शिता जरूरी है। राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों को भी पारदर्शी व्यवहार की शुरुआत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं।

चाहे दूध उत्पादन प्राइमरी समिति हो या मछुआरों से संबंधित समिति। गांवों की प्रकृति जैसी होगी वैसी ही समितियों का गठन कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पैक्सों को कंप्यूटराइज करने पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे निबंधन से लेकर ऑडिट तक सारे काम ऑनलाइन होने लगेंगे। पैक्स ही राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों की आत्मा है। अगर सहकारी बैंकों को मजबूत करना है तो पैक्सों को मजबूत करना होगा। इसके लिए पैक्सों को नई तकनीक के लिए तैयार किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सहकारी बैंकों का निरंतर आधुनिकीकरण और कार्य क्षमता का विकास हो रहा है। सहकारी व्यवस्था ने पूरे देश के किसानों और कृषि में नई जान फूंकी है। सहकारी बैंकों ने जल प्रबंधन से लेकर कृषि एवं गांवों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जा रहा है। अलग मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी यही है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर लेना है। अगले पांच वर्ष सहकारिता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सरकार गरीब, दलित आदिवासी और महिला का सम विकास चाहती है। सरकार ने करके दिखाया भी है। सहकारी क्षेत्र में इफको, कृभको और अमूल जैसी संस्थाओं ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

किसानों की बिना सहमति के फसल बीमा नहीं काटने की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सांचौर । क्षेत्र के किसानों एवं संयुक्त किसान मोर्चा सांचौर के प्रतिनिधि मंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिवाड़ा के प्रबंधक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मोर्चा के जिला अध्यक्ष ईशाराराम बिश्नोई ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा सांचौर जिला मुख्यालय पर हुई आम सभा में लिए गए निर्णय अनुसार सभी बैंकों को ज्ञापन देकर किसानों की सूचना के आधार पर आगामी रबी सीजन का फसल बीमा काटने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि रबी 2024 का प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम संबंधित किसानों की लिखित सहमति पर ही बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम काटा जाए। अधिकांश किसानों की बिना सहमति से बैंकों

द्वारा करोड़ों रुपए पिछले तीन साल से किसानों का बीमा प्रीमियम काट लिया गया और संबंधित काश्तकार को पता ही नहीं होता है कि उनके किस फसलों का बीमा प्रीमियम काटा गया और कौनसे खसरे में कितने रकबे में कौन सी फसल बोई हुई है। बीमा कंपनियां फसलों में हुए नुकसान की स्थिति में जब काश्तकार के खेत में मौके पर सर्वे के लिए आती है तो वहां पर दूसरी फसलें बोई हुई होती है।ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बुवाई में और बैंक की बीमा पॉलिसी प्रीमियम में अलग-अलग होने के कारण बीमा क्लेम नहीं मिल पाता है। किसान मोर्चा उपाध्यक्ष विरद सिह चौहान ने बताया कि किसानों की लिखित सहमति और बुवाई प्रमाण पत्र के आधार पर ही बीमा प्रीमियम काटा जाए ताकि संबंधित काश्तकार को अपनी फसलों और बुवाई की पूर्ण जानकारी रहेगी। धीमाराम खिलेरी ने बताया कि काश्तकारों की सहमति से बीमा की सरलीकरण से आम किसानों के फसलों में होने वाले नुकसान का पूरा क्लेम मिल सकेगा।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा भारतः सीतारमण

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि बैंकों को वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 6.12 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए एमएसएमई को 7 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखना चाहिए। वह आज मुंबई में 11वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में मुय भाषण देते हुए बोल रही थीं। इसका विषय था 'विकसित भारत की आकांक्षा को वास्तविकता बनाना'। सुश्री सीतारमण ने कहा कि 2013-14 में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। उसके बाद अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और 2021-22 तक यह 5वें स्थान पर पहुंच गई। उन्होंने उमीद जताई कि अगले कुछ सालों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।

जिला पर्यावरण समिति की बैठक सपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। जिला कलक्टर प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलक्टर प्रदीप के. गावंडे ने जिले में ग्रेनाइट स्लरी की अवैध डंपिंग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुचारू रूप से निस्तारण करने की बात कही। बैठक में जिला कलक्टर ने प्रदूषण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता को जिले में आमजन को वायु गुणवत्ता की जानकारी मिल सकें इसके लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक और एक्यूआई के मापन के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर एवं नगर परिषद में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्थापित स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे गुणवत्ता सूचकांकों को लेकर विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिले में एफएसटीपी कार्यों पर चर्चा के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के रोकथाम के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा आमजन को जागरूक कर कपड़े, जूट व कागज से बनी कैरी बैग्स का उपयोग करने को लेकर प्रोत्साहित करने की बात कही। इस अवसर पर उप वन संरक्षक देवेंद्र सिंह भाटी, जिला परिवहन अधिकारी सीएल मालवीय, सीएमएचओ डॉ. रमाशंकर भारती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला और युवाओं के मामले में नजरिया बदलने की आवश्यकता - संघानी

सहकारी संस्थाओं के संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका -सहकारिता राज्य मंत्री

जयपुर,। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल है जो जाति, वर्ग, रंग या भाषा के परे जाकर समाज के सभी वर्गों और समुदायों को उनकी आवश्यकताओं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता हमेशा सभी वर्गों के मध्य अवसरों में समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी को कम करने एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिये उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसलिये सहकारिता के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास संभव है। नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान सहकारी संघ द्वारा 71वें राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ''महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिये सहकारिता'' विषय पर अपने संबोधन में श्री दक ने कहा कि किसी भी सहकारी संस्था के प्रभावी संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के मध्य समन्वयय के साथ-साथ अपने-अपने कार्य दायित्वों के निर्धारण और उनके निर्वहन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सहकारी कानून, नियम और संस्था के उपनियमों की पूरी जानकारी है तो वह अपने अनुभव और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर संस्था के संचालन में महती भूमिका निभा सकते हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिये सस्ती ब्याज दरों पर सुलभ ऋण ऋण मुहैया कराने और उत्पादों के विक्रय के लिये प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध

कराना, दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर पहली बार 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान, पहली बार अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, नये सदस्यों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण देना, प्रत्येक पंचायत समिति में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन आदि जैसे कदम उठाये हैं। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री द्वारा नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति की ड्रोन दीदी के नाम से जाने जानी वाली सुश्री सरोज राठौड और उनकी साथिन को शॉल ओढाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य सहकारी संघ के प्रशासक श्री भोमाराम द्वारा प्रदेश में सहकारिता के विकास और उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया तथा अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आर. एस. चौहान द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से सहकारजनों सहित महिलाओं और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया।

महिला और युवाओं के मामले में नजरिया बदलने की आवश्यकता - संघानी

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी ने कहा कि हमें महिला और युवाओं के मामले में नजरिया बदलने की आवश्यकता है कि वे कमजोर हैं। हम महिलाओं और देश के युवाओं को अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे उनकी योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता है। उन्हें मौका देंगे तो उनकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा और वे अपने विकास के साथ-साथ समाज और देश के विकास में नये रंग भर देंगे। इसलिये उन्होंने सहकारजन का आह्वान किया कि वे सहकारी सोसायटियों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं की योग्यता के आधार पर अवसर तलाशे और प्लेटफार्म उपलब्ध करावें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक सोसायटियों के लिये मॉडल उपनियमों के संहिताकरण का कार्य किया जा रहा है और उनके लिये अब 50 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें ऐसी सोसायटियां कार्य कर सकती हैं। श्री संघानी ने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर अब किसान या आर्टिजन अपने उत्पादों का पोर्टल के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकता है, उसे इसके लिये किसी बिचौलिये की आवश्यकता नहीं है।

पैक्स कप्यूटराईजेशन और उनके गो-लाइव का कार्य तेजी से किया जा रहा

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि महिला और युवाओं की शक्ति अपार हैं। लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण उनकी योग्यता का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की महिलाओं को पर्याप्त अवसर, उद्यमशीलता के लिये प्रशिक्षण, नवीन तकनीक का ज्ञान और उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जावे तो वे विकास नये सोपान गढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पैक्स कप्यूटराईजेशन और उनके गो-लाइव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से प्रदेश में ग्राम स्तर पर पारदर्शिता स्थापित होगी और त्वरित बैंकिंग एवं ई-मित्र जैसी सुविधायें मिल सकेंगी।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, रविवार, 1 दिसंबर 2024
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

उपविधियों के उपबंधों के विरूद्ध होने की स्थिती में संकल्पों को विखण्डित करने की शक्ति रजिस्ट्रार के पास

सहकारी संस्थाओं की आमसभा एवं संचालक मण्डल बैठक में नही होती नियमों की पालना, अब निर्देश जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में आमसभा एवं संचालक मण्डल की बैठक का आयोजन करते समय राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 एवं 2003 के नियमों की पालना नहीं की जाती है। अब सहकारिता विभाग पंजीयक ने इस संबंध में आदेश जारी कर सहकारी संस्थाओं की बैठके आयोजित करते समय राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं नियम 2003 के उपनियमों की पूर्ण रूप से पालना करने के निर्देश दिए गए है। जिसमें सहकारी समिति की बैठक का नोटिस चस्पा करने, राजकीय प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित करने, सहकारी समिति के लेखे तैयार होने के पश्चात तीन मास के भीत्तर वार्षिक साधारण बैठक आहुत करने के निर्देश दिए गए है। इसी प्रकार विशेष साधारण बैठक मे कोरम का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा यदि किसी सहकारी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरूद्ध है या सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या इस अधिनियम, नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विरूद्ध होने की स्थिती में संकल्पों को विखण्डित करने की शक्ति रजिस्ट्रार के पास होगी ।

समिति की बैठक का नोटिस करना होगा चस्पा

रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी समिति की बैठक का नोटिस, बैठक का स्थान, तारीख और समय, साथ ही बैठक में किये जाने वाले कारबार या ऐजेंडा की कार्यसूची समिति के प्रत्येक सदस्य को बैठक की कालावधि से कम से कम सात दिन पूर्व विनिर्दिष्ट करने के साथ-साथ यदि कोई भी अति आवश्यक कारबार, जिसे नोटिस के साथ भेजी गयी कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसे बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों की सहमति से लोन के पश्चात उस पर विचार किया जाएगा ।

वार्षिक साधारण बैठक तीन मास की कालावधि में हो आहुत

रजिस्ट्रार के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाओं की प्रवृत्त नियमों के अधीन वर्ष के अपने लेखे तैयार करने के लिए नियम तारीख के पश्चात आगामी तीन मास की कालावधि के भीत्तर-भीत्तर सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक आहुत करनी होगी । साथ ही संचालक मण्डल की बैठकों में राजकीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, वही अगर बैठक में लिये गये प्रस्तावों के संबंध में यदि किसी राजकीय प्रतिनिधि द्वारा असहमति व्यक्त की जाती हैं, तो उसकी सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र है.

सिर्फ सहकारी सेक्टर में ही 11 करोड़ लोगों को जॉब देने की क्षमता, दावे में कितनी सच्चाई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली. देश के सिर्फ एक सेक्टर पर ही फोकस कर लिया जाए तो बेरोजगारी संकट पूरी तरह खत्म हो सकता है. प्रबंधन परामर्श कंपनी प्राइमस पार्टनर्स ने जारी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है. इसमें कहा गया है कि भारत के सहकारी क्षेत्र में ही साल 2030 तक प्रत्यक्ष रूप से 5.5 करोड़ नौकरियां और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है, जो देश से बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह समाप्त कर सकता है. सहकारी क्षेत्र पर जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सहकारी तंत्र वैश्विक स्तर पर 30 लाख सहकारी समितियों में से करीब 30 प्रतिशत यानी करीब 9 लाख समितियों का प्रतिनिधित्व करता है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सहकारी क्षेत्र आशा और क्षमता की किरण बना हुआ है.

भारत सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र

भारत दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र है. यहां आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल के रूप में दिग्गज सहकारी कंपनी है. इसके अलावा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसायटी और लिज्जत पापड़ जैसी जानी-मानी कंपनियां भी इस क्षेत्र में काम करती हैं. केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने देश के सहकारी सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं.

5.5 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ

रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहकारी तंत्रों में से एक के साथ भारत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र की अपार क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए तैयार है. भविष्य की ओर देखते हुए सहकारी समितियों में 2030 तक 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है, जिससे रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका और बढ़ जाएगी.

जीडीपी में 5 फीसदी योगदान

यह रिपोर्ट भारत के सहकारी क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को भी दर्शाती है. इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर उनका असर भी उतना ही प्रभावशाली है. इनका 2030 तक संभावित योगदान 3 से बढ़कर 5 प्रतिशत तक हो सकता है. प्रत्यक्ष तथा स्वरोजगार दोनों की बात करें तो यह 10 प्रतिशत से अधिक हो सकता है.

घोटाला: गेहूं, चना, सरसो, मूंग, मूंगफली व सोयाबीन खरीद का मामला

19 केवीएसएस ने किया एमएसपी से खरीद में 24.85 करोड़ का गबन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । किसानों को उनकी मेहनत की पाई-पाई दिलाने के लिए सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है। उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करती है। लेकिन इस खरीद को सहकारिता विभाग के अफसरों, बाबुओं और ठेकेदारों ने कमाई का जरिया बना रखा है।

भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ के प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के दौरान प्रदेश में 19 क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने किसानों से गेहूं, चना, सरसो, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन सहित अन्य जींस की खरीद में 24 करोड़ 85 लाख 46 हजार 383 रुपए का गबन किया गया। इसमें अब तक केवल 97 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है। यानी सहकारिता विभाग अब तक एक करोड़ रुपए भी पूरा वसूल नहीं कर पाया है।

कोऑपरेटिव मैनेजर, ठेकेदार, खरीद केंद्र प्रभारी, कप्यूटर ऑपरेटर तक घोटाले में शामिल

अब तक वसूली केवल 97 लाख रुपए

जोधपुर में 2.71 करोड़ रुपए का गबन

जोधपुर मार्केटिंग सोसायटी में 2019- 20 में ठेकेदार धर्मेंद्र काला की ओर से 1.36 करोड़ का गबन किया गया। फलोदी मार्केटिंग सोसायटी में 2019- 20 के दौरान मैनेजर मुरली मनोहर व्यास, केंद्र प्रभारी हरीसिंह, मोहनलाल और देवीसिंह ने मिलकर 1.24 करोड़ रुपए का माल खुर्द-बुर्द कर दिया। बाप मार्केटिंग सोसायटी में मैनेजर मुरली मनोहर व्यास, खरीद केंद्र प्रभारी दिलीप सिंह, कप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर 11.05 लाख का घोटाला किया, हालांकि यह राशि वसूल की जा चुकी है।

इन समितियों ने किया गबन

सरवाड़, सरवाड़, डेगाना, खण्डार, बहरोड़, जोधपुर, फलोदी, बाप, रायपुर, जैतारण, बज्जू, सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बेरियावाली, कोलायत, सूजानगढ़, डूंगरगढ़। (इसमें से बाप, डूंगरगढ़ और सुजानगढ (श्रीराम एजेंसी) से वसूली की जा चुकी है। शेष से वसूली बाकी है। इसमें मैनेजर, खरीद केंद्र प्रभारी, हैंडलिंग व ट्रांसपोर्ट ठेकेदार, संविदा कार्मिक व कप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।)

पशुपालन शासन सचिव ने किया औचक निरीक्षण

जयपुर, डॉ समित शर्मा, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग ने अपने सीकर प्रवास के दौरान जिले की पशु चिकित्सा संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा जिला स्तरीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रातः 9:00 बजे ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस पलसाना का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनुपस्थित पाए गए लैब असिस्टेंट को डॉ. शर्मा ने निलबित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय में साफ सफाई, व्यवस्था तथा सामान व उपकरण के संधारण एवं अनुपयोगी समान के निस्तारण नहीं किये जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए इन्हें शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक पलसाना में स्थापित मोबाइल वेटरनरी यूनिट के पशु चिकित्सक व पशुधन सहायक उपस्थित मिले परंतु एमवीयू का वाहन चालक नदारद पाया गया। बार-बार निर्देश के उपरांत भी मोबाइल यूनिट का वाहन 9:20 बजे तक ब्लॉक कार्यालय पर नहीं लाया गया। इस पर शासन सचिव डॉ शर्मा ने निदेशक पशुपालन एवं योजना प्रभारी को सेवा प्रदाता कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर कार्यालय परिसर में संचालित जिला कार्यालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, सीकर तथा जिला रोग निदान प्रयोगशाला का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों में से छह कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। डॉ. शर्मा ने समय पालन के संबंध में उक्त कार्मिकों की वस्तुस्थिति के बारे में विश्लेषण कर मौके से ही अनुपस्थित पाए गए सभी कार्मिकों को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए।

दांता ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दांता

पंचायत समिति - सरनाऊ, जिला - सांचौर

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

श्री अमलुराम मांजू
अध्यक्ष

श्री भगराज मांजू
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

एकमुश्त समाधान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की सांचौर शाखा में सपर्क करें।

411 शिक्षकों के स्थायीकरण का निर्णय

जालोर । जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्थापना समिति जालोर की बैठक में दो वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण कर चुके अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम व द्वितीय के 411 शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला परिषद के मुय कार्यकारी अधिकारी नन्दकिशोर राजोरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा व जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक भैराराम उपस्थित रहे।

राजस्थान में उर्वरक की ऐसी होगी नई व्यवस्था, ताकि किसानों को न हो परेशानी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के कृषि विभाग ने यूरिया और डीएपी उर्वरक के वितरण के लिए नई व्यवस्था की है ताकि राज्य के किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े। बता दें कि रबी सीजन में खाद की मांग ज्यादा है लेकिन सरकारी स्तर पर खाद की उपल धता कभी होती है तो कभी नहीं होती है इसलिए वहां के किसानों को परेशान होना पड़ता है लेकिन अब कृषि विभाग ने वितरण व्यवस्था परमिट सिस्टम से करने का फैसला लिया है। रबी सीजन में डीएपी और यूरिया उर्वरक की मांग एवं आपूर्ति के गणित को देखते हुए कृषि विभाग ने यूरिया व डीएपी उर्वरक का वितरण व्यवस्था परमिट सिस्टम से करने का निर्णय किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए समस्त थोक व खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को पाबंद किया है कि डीएपी व यूरिया उर्वरक का विलय जिले एवं कार्यक्षेत्र से बाहर वितरण किसी भी हालत में नहीं किया जाए। जिले में रबी में सरसों, चना, धनिया, मसूर व गेंहू की रिकॉर्ड बुवाई होती है तथा डीएपी और यूरिया की आपूर्ति मांग की तुलना में कम हो रही है। इस कारण विभाग समय से पहले ही सतर्क हो चुका है। इसके लिए प्रत्येक किसान को अधिकतम 10 बैग या इससे कम अथवा उपल धता के अनुरूप डीएपी व यूरिया उर्वरक का विक्रय किया जाए।

उर्वरक विक्रेताओं की ओर से जिन किसानों को डीएपी या यूरिया की उर्वरक विक्रय किया जा रहा है। उनके आधार कार्ड की छाया प्रति एवं किसान होने संबंधी दस्तावेज (जमाबंदी, पासबुक) आदि हस्ताक्षरित छायाप्रति प्राप्त कर रिकॉर्ड संधारित किया जाए। डीएपी व यूरिया उर्वरक विक्रय किए जाने के उपरांत उसी समय संबंधित किसान को पता बिल उपल ध करवाते हुए बिल पर किसान का नाम,पूर्ण पता मय मोबाइल नंबर के साथ-साथ उर्वरक का नाम एवं बैच नंबर का अंकन करना सुनिश्चित किया जाए ताकि वितरण का भौतिक सत्यापन करवाया जा सकें। सहायक निदेशक राजेश विजय ने बताया कि इस बार विभाग के द्वारा डीएपी, यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर चेक पोस्ट बनाई जाएगी। इन चेक पोस्ट का उद्देश्य है कि बॉर्डर एरिया से डीएपी, यूरिया का विक्रय जिले व राज्य से बाहर होने से रोकने के लिए किया जाएगा।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाए

श्री हनुमानसिंह राजावत

जालोर जिले की हरजी ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक एवं यूनियन जालोर जिला इकाई अध्यक्ष

श्री हनुमानसिंह राजावत

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

शुभेच्छु

मांगीलाल विश्नोई
व्यवस्थापक अरणाय जीएसएस

लक्ष्मणराम पुरोहित
व्यवस्थापक सरवाना जीएसएस

हनुमानसिंह जाट
व्यवस्थापक टांपी जीएसएस

डायाराम देवासी
व्यवस्थापक नरसाणा जीएसएस

तेजसिंह राजपुरोहित
व्यवस्थापक सेलड़ी जीएसएस

पोकराराम विश्नोई
व्यवस्थापक लाछीवाड़ जीएसएस

अधिकारियों ने निरीक्षण कर देखी आवश्यक व्यवस्थाएँ

जालोर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार घुम्मन्तु समुदाय (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु) के विकास के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे-वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, घुमन्तु जाति पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि जारी करने तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए नगर पालिका आहोर, ग्राम पंचायत जसवन्तपुरा व बिशनगढ़ में सहायता शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजीव कुमार सुथार ने बताया कि शिविरों में प्राप्त वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के 15, मतदाता पहचान पत्र के 3,, आधार कार्ड के 11, जनाधार कार्ड के 9, राशनकार्ड के 1, जाति प्रमाण पत्र के 3, घुमन्तु पहचान पत्र के 12, पालनहार के 12 एवं विभिन्न योजनाओं सहित कुल 64 आवेदनों का निस्तारण किया गया। पात्र व्यक्ति यों को पेंशन, पालनहार व विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करवाकर स्वीकृतियां जारी की गई। शिविरों में घुमन्तु समुदाय के लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान राजस्व, पंचायतीराज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कार्मिक उपस्थित रहे।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध 12 सहकारिता सेवा के अधिकारी अधिक नियुक्त

शीर्ष सहकारी संस्थाओं में नियुक्त अधिकारियों की अधिकत्तम सेवा अवधि का कोई नियम निर्धारित नहीं

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में शीर्ष सहकारी संस्था यथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक , राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में राजस्थान सहकारिता सेवा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिक अधिकारी नियुक्त हैं, इतना ही नहीं शीर्ष सहकारी संस्थाओं में स्वीकृत पदों पर नियुक्त अधिकारियों की अधिकत्तम सेवा अवधि के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं हैं, ऐसा सहकारिता विभाग ने विधायक अरुण चौधरी के सोलहवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में 13 जुलाई 2024 को लगाए गए अतारांकित प्रश्न के प्रतिउत्त र में लिखित जवाब दिया है। इसके अलावा विधायक ने शीर्ष सहकारी संस्थाओं में नियुक्ति के मापदण्ड का विवरण भी सदन पटल के जरिए मांगा था, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परिपत्र में वर्णितानुसार हैं, वही शेष शीर्ष सहकारी संस्थाओं में प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कैडर / स्टाफ स्ट्रेन्थ के अनुसार राज्य सरकार एवं संस्था द्वारा की जाती है। विधायक ने स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्त अधिकारियों की सूची भी मांगी थी, जो सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं, जिसके अनुसार स्वीकृत पदों के विरुद्ध 12 सहकारिता सेवा के अधिकारी अधिक नियुक्त हैं, जिसमें कॉनफैड में चार और अपेक्स बैंक में भी चार, राजफैड में तीन तथा आरसीडीएफ में एक सहकारिता सेवा का अधिकारी स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिक नियुक्त हैं ।

प्रदेश में कोई निजी सहकारी बैंक पंजीकृत नहीं

विधायक अरुण चौधरी ने एक अन्य अतारांकित प्रश्न सोलहवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में कर राज्य की निजी सहकारी बैंक एवं सरकार की ओर से संचालित सहकारी बैंक और उनमें कार्यरत स्थायी एवं अस्थाई कार्मिकों का विवरण मांगा था । सहकारिता विभाग से प्रश्न के प्रतिउत्तर में प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोई निजी सहकारी बैंक पंजीकृत नहीं है, प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक एवं 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यरत है। वही राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं 29 केंद्रीय सहकारी बैंक में 1660 स्थाई एवं 2 अस्थाई कार्मिक कार्यरत है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में 40 स्थाई तथा 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में 164 स्थाई एवं 1 अस्थाई कार्मिक कार्यरत है।

मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक
विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें
Contact Number 9602473302, 7976323829

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।